भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2467

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति

2467. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा संभारतंत्र पार्क, भंडारण और मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क विकसित करने में क्या उपलब्धियां अर्जित की गई हैं;

(ख): संभारतंत्र लागत एवं पारगमन समय को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने पर उक्त नीति के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और संभारतंत्र प्रदर्शन सूचकांक में कितना सुधार हुआ है;

(ग): राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति के कार्यान्वयन के दौरान सामने आई प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ): सरकार द्वारा डिजिटल रूपांतरण हेतु और अधिक सहायता देने, कार्यबल का कौशल उन्नयन करने और नीति के संवहनीय लक्ष्यों के परिदृश्य में हरित संभारतंत्र प्रविधियों को और अधिक अपनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के तहत, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने, परिसंपत्तियों का मानकीकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण आदि जैसी प्रमुख चुनौतियों को दूर करने और देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न कार्रवाई शुरू की गई हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:

1. कोयला क्षेत्र में कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए सेक्टोरल प्लान (एसपीईएल) अधिसूचित किया गया है।

2. 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी-अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित किया है। अधिसूचित नीतियों का विवरण https://dpiit.gov.in/logistics/state-logistics-policies लिंक पर उपलब्ध है।

3. अंतर-मंत्रालयी सेवा सुधार समूह (एसआईजी) का गठन 14 मार्च, 2023 को किया गया है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के व्यापार संघों की भागीदारी के साथ इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और दक्षता में सुधार के लिए एक सुदृढ़ तंत्र तैयार किया जा रहा है।

4. लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2023 का 5वां संस्करण 16 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया।

5. वर्ष 2022 में वेयरहाउसिंग मानकों पर ई-हैंडबुक लॉन्च की गई।

रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलें, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और माल ढुलाई के डिजिटलीकरण के प्रयास, साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एयर कार्गो सुविधाओं के विकास, और मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) जैसी डिजिटल पहलों से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, आवागमन समय में सुधार करने तथा समग्र आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। यह नीति पीएम गति शक्ति जैसी अवसंरचना आधारित पहलों से भी जुड़ी हुई है जो जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकीकृत अवसंरचना नेटवर्क बनाने पर केंद्रित हैं।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 54 से छह पायदान के सुधार के साथ वर्ष 2023 में 38 हो गई है। विश्व बैंक ने एलपीआई 2023 रिपोर्ट में भारत के प्रयासों की सराहना की, इन प्रयासों में देश के दोनों तटों के बंदरगाहों को भीतरी इलाकों में स्थित आर्थिक केंद्रों से जोड़ने के लिए सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण शामिल है।

(घ) और (ङ) : एक डिजिटल गेटवे - यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) को उद्योग के हितधारकों की पहुंच, एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स-संबंधित डेटासेट तक बनाने के लिए, वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म अनुरोध करने और उसका उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था पर कार्य करता है और वर्तमान में 11 मंत्रालयों की 39 प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जो 125 एपीआई के माध्यम से 1,800 से अधिक डेटा फ़ील्ड तक पहुंच प्रदान करता है। भारत के कंटेनर वाले एक्जिम कार्गो की 100% ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हेतु, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) को विकसित किया गया है। एलडीबी भारत में एक्जिम कंटेनर मूवमेंट की रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को, एक विशेष लॉजिस्टिक्स पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एसओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और इस डोमेन में पहले ही 8 पाठ्यक्रम लॉन्च किए जा चुके हैं। 08 मई 2024 को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), भोपाल में सिटी लॉजिस्टिक्स के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की गई है। कौशल विकास के लिए कुल 37 योग्यता पैक (क्यूपी) चालू हैं, जिनमें वित्त वर्ष 24-25 में लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएसएससी) के साथ मिलकर तैयार किए गए 7 क्यूपी शामिल हैं।

जागरूकता पैदा करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित मूल स्थान-गंतव्य के बीच परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच जीएचजी उत्सर्जन की गणना और तुलना करने के लिए फ्रेट ग्रीनहाउस गैस कैलकुलेटर विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने ऐसे फ्रेट ग्राहकों को "रेल ग्रीन पॉइंट" आवंटित करने की अवधारणा शुरू की है, जो कार्बन उत्सर्जन की अपेक्षित बचत का विवरण प्रदान करते हैं।

*****